मई 2019

1. विशेष श्रेणी की स्थिति (SCS) क्या है

- एससीएस की अवधारणा 1969 में सामने आई जब गाडगिल फॉर्मूला (जो राज्यों को केंद्रीय सहायता निर्धारित करता है) को मंजूरी दी गई थी.
- संविधान में विशेष श्रेणी की स्थिति का कोई प्रावधान नहीं है; केंद्र सरकार उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो दूसरों के खिलाफ तुलनात्मक नुकसान में हैं.
- एनडीसी (नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल) ने राज्यों की कई विशेषताओं के आधार पर यह दर्जा दिया, जिसमें शामिल हैं-
  (a) पहाड़ी और कठिनाई भरा इलाका
  (b) कम जनसंख्या घनत्व या बड़े पैमाने पर जनजातीय आबादी की उपस्थिति
  (c) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान
  (d) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन
  (e) राज्य वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति.
- विशेष दर्जा भारत के संविधान द्वारा संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित एक अधिनियम के माध्यम से दिया जाता है, जैसा कि जम्मू और कश्मीर के मामले में है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा दिया जाता है, सरकार का एक प्रशासनिक निकाय.

SCS राज्यों को किस प्रकार की सहायता प्राप्त होती है?

- केंद्र सरकार 2009-10 के अंत तक इन राज्यों को अपने योजना व्यय का 30 प्रतिशत आवंटित करती है. (गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला).
- NITI आयोग के गठन और SCS के लिए केंद्रीय योजना सहायता के बाद सभी राज्यों के लिए विभाज्य पूल के बढ़ते विचलन में राज्यों को शामिल किया गया है (13 वीं एफसी सिफारिशों में 32% से 42% तक) और अब किसी भी योजना व्यय में दिखाई नहीं देते हैं
- 14 FC ने "वन कवर" जैसे चर को भी मानदंड में शामिल करने की सिफारिश की, जिसमें 7.5 का मानदंड था और जो उत्तर-पूर्वी राज्यों को लाभ दे सकता था जिन्हें पहले SCS सहायता दी गई थी.
- एससीएस राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सहायता 90% केंद्रीय हिस्से और 10% राज्य की हिस्सेदारी के साथ दी गई थी.

कौन से राज्य SCS का दर्जा मांग रहे हैं?

- ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश को एससीएस का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उनके द्वारा मानदंड पूरा नहीं होने के कारण अनुमति नहीं मिली है.

कितने राज्यों को SCS का दर्जा प्रदान किया गया है?

- 29 में से 11 राज्यों में बेहतर-संतुलित विकास के लिए निधि प्रवाह को लक्षित करने के लिए "विशेष श्रेणी के राज्यों" की स्थिति के लिए NDC ने सहमती जताई है.
- वे हैं -

  (a) पूर्वोत्तर राज्यों के सात राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा)

  (b) सिक्किम

  (c) जम्मू और कश्मीर

  (d) हिमाचल प्रदेश

  (e) उत्तराखंड.
- जम्मू और कश्मीर विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य था, और अन्य 10 राज्यों को वर्षों में जोड़ा गया था, उत्तराखंड 2010 में अंतिम था.

2. डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट: भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भारी कमी है, खासकर बिहार, झारखंड, यू.पी. और राजस्थान में

- डब्ल्यूएचओ ने 'डब्ल्यूएचओ साउथ-ईस्ट एशिया जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ 'में 2026 तक भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए भविष्य की आवश्यकता और भविष्य में आवश्यकताओं के अंतराल के बारे में एक शोध पत्र प्रकाशित किया है.
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बिहार, झारखंड, यू.पी. (उत्तर प्रदेश) और राजस्थान में दिल्ली, केरल, पंजाब और गुजरात की तुलना में सबसे खराब अनुपात है जो अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं.
- डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वर्ष 2030 तक दक्षिण पूर्व एशिया को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य सेवा में 50% वृद्धि की आवश्यकता है.
- भारत के स्वास्थ्य कर्मचारियों को मोटे तौर पर 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिन्हें इस प्रकार नामित किया गया है:

  (a) डॉक्टर (एलोपैथिक, वैकल्पिक चिकित्सा)

  (b) नर्सिंग और दाई का काम करने वाले पेशेवर

(c) सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर (चिकित्सा, गैर-चिकित्सा)
(d) फार्मासिस्ट
(e) दंत चिकित्सक
(f) पैरामेडिकल वर्कर्स (संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर)
(g) ग्रास-रूट वर्कर्स (फ्रंटलाइन वर्कर्स)
(h) सहायक कर्मचारी

- 2008 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वीकृत पदों में रिक्तियों के आधार पर: 18% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टर के थे.